नईदुनिया

भोपाल, 28 नवम्बर 2026

भारत-अमेरिका बातचीत में पुरानी अड़चनें दूर होने के संकेत

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की राह आसान शुल्क और बाजार पहुंच के मुद्दों पर बनी सहमति

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार समझौते की बातचीत अब अंतिम चरण के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति हुई है और बातचीत में पहले बाधा बने मुद्दों पर समाधान के रास्ते बन रहे हैं।

अमेरिका ने हाल ही में भारत सहित 14 व्यापारिक साझेदारों पर नए आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि कुछ देश जरूरत से अधिक उत्पादन कर कम कीमत पर वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा है। प्रस्ताव के तहत भारत सहित सात देशों पर 25 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जा सकता है।



समझौते पर जल्द हस्ताक्षर होने की उम्मीद

कारोबारियों और निवेशकों को स्थिर व्यापारिक वातावरण मिलेगा

वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग ने कहा कि समझौते पर जल्द हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे दोनों देशों के कारोबारियों और निवेशकों को स्थिर व्यापारिक वातावरण मिलेगा। प्रस्तावित समझौते के तहत वियतनामी वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क में भी कमी आने की संभावना है।

17 प्रतिशत तक आने की संभावना

यदि भारत और अमेरिका के बीच समझौता होता है, तो भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क घटकर लगभग 17 प्रतिशत तक आने की संभावना जताई गई है। हालांकि, दोनों देशों ने अभी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बाजार तक पहुंच, आयात शुल्क और अन्य व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत जारी है। समझौता होने से भारतीय निर्यातकों और अमेरिकी बाजार में कारोबार करने वाली कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने व्यापार कानून की धारा 301 के तहत विभिन्न देशों के विनिर्माण क्षेत्र की जांच की है। इस जांच में अधिक उत्पादन और उसके अमेरिकी उद्योगों पर प्रभाव का आकलन किया गया। इसी आधार पर नए शुल्क लगाने का प्रस्ताव सामने आया है। भारत और अमेरिका ने फरवरी 2026 में अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। इसके बाद भारतीय वस्तुओं पर पहले लगाए गए शुल्क में बदलाव किया गया था। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यापक शुल्क व्यवस्था को अमान्य किए जाने के बाद व्यापारिक बातचीत की प्रक्रिया दोबारा आगे बढ़ी। भारत चाहता है कि उसके उत्पादों पर अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क लगाया जाए, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इस बीच वियतनाम ने भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत लगभग पूरी होने की जानकारी दी है।

शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 83,339 और निफ्टी 25,607 पर बंद

- सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली
- विदेशी निवेशकों ने पिछले सात दिनों में 15,995 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे



नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 989 अंक यानी 1.17 प्रतिशत टूटकर 83,339 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 277 अंक गिरकर 25,607 अंक पर आ गया। कारोबार के दौरान धातु कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। बाजार में गिरावट के चलते बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार मूल्य घटकर 513 लाख करोड़ रुपये रह गया। पिछले कारोबारी दिन यह करीब 514 लाख करोड़ रुपये था।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर स्पष्टता नहीं होने से निवेशकों की चिंता बढ़ी। अमेरिकी आयात शुल्क को लेकर अनिश्चितता का असर बाजार की धारणा पर पड़ा। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट ने प्रमुख सूचकांकों पर दबाव बढ़ाया। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी बाजार के लिए चिंता का विषय रही। ब्रेंट कच्चा तेल 0.56 प्रतिशत बढ़कर 97 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। इससे भारत में महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा दिसंबर में अमेरिकी केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दर संबंधी निर्णयों से पहले निवेशक सतर्क रहे।

इन फैसलों का असर बाजार में धन की उपलब्धता और विदेशी निवेश की दिशा पर पड़ सकता है। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स के शेयर बाजार में गिरावट के साथ सूचीबद्ध हुए। बीएसई पर शेयर 2.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 133.15 रुपये और एनएसई पर 1.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 134 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी के शेयर का निर्गम मूल्य 129 से 136 रुपये था।

इसके शेयर निर्गम को 1.52 गुना अभिदान मिला था। विदेशी निवेशकों ने पिछले सात दिनों में 15,995 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी 6,889 करोड़ रुपये रही। शुक्रवार को एशियाई बाजारों में तेजी रही। दक्षिण कोरिया, जापान और हांगकांग के बाजार बढ़त के साथ कारोबार करते रहे। इससे पहले अमेरिकी बाजारों में मिला-जुला रुख रहा था।

खास-खबरें

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट की पेशकश अगले सप्ताह

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: जेएसडब्ल्यू मोटर्स तीन दिसंबर को भारतीय वाहन बाजार में अपनी पहली गाड़ी कॉम्बैट पेश करने जा रही है। कंपनी ने इसके साथ ही विशेष संस्करण 'पायनियर्स 500' की घोषणा की है, जिसकी केवल 500 इकाइयां उपलब्ध होंगी। इस विशेष संस्करण में अलग पहचान वाले डिजाइन, ग्राहक के नाम की पट्टिका और अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। पायनियर्स 500 संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इच्छुक ग्राहकों को पहचान सत्यापन के बाद एक लाख रुपये की पंजीकरण राशि जमा करनी होगी। इसके बाद निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक का मूल्य प्रस्ताव देना होगा। चयन केवल पहले आवेदन करने के आधार पर नहीं होगा, बल्कि प्राप्त मूल्य प्रस्तावों के आधार पर 500 ग्राहकों का चयन किया जाएगा। कंपनी के अनुसार, विशेष संस्करण की गाड़ियों में अलग पहचान वाला चिह्न, ग्राहक के नाम की पट्टिका और विशिष्ट क्रमांक दिया जाएगा। इसके अलावा चुनिंदा ग्राहकों को विशेष सेवाएं, वाहन सौंपने का अलग अनुभव, निजी ग्राहक समुदाय से जुड़ने का अवसर और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट कंपनी की पहली गाड़ी होगी और तीन दिसंबर को इसका आधिकारिक पदार्पण प्रस्तावित है। विशेष संस्करण की आपूर्ति जनवरी 2027 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी गाड़ी की आधिकारिक कीमत और सभी तकनीकी विशेषताओं का खुलासा नहीं किया है। कॉम्बैट के जरिए जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय वाहन बाजार में अपनी नई शुरुआत करने जा रही है।

चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर कानूनी विवाद

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। उनकी पुनर्नियुक्ति के खिलाफ टाटा ट्रस्ट की याचिका पर 27 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने नियुक्ति के फैसले को कंपनी के नियमों के विरुद्ध बताते हुए न्यायालय का रुख किया है।

ट्रस्ट का आरोप है कि 17 सितंबर को हुई टाटा संस की संचालक मंडल बैठक में चंद्रशेखरन को अगले पांच वर्षों के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय नियमों के अनुरूप नहीं था। ट्रस्ट इस नियुक्ति को रद्द कराने की मांग कर रहा है। न्यायालय जाने के फैसले पर ट्रस्ट के पांच सदस्यों में एकमत नहीं था। तीन सदस्यों नोएल टाटा, नेविल टाटा और भास्कर भट ने कानूनी कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह इसके विरोध में रहे। 17 सितंबर की बैठक में चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर मतभेद सामने आए थे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे हरीश मनवानी ने बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का इस्तेमाल कर नियुक्ति के पक्ष में फैसला दिया था।

विवाद कंपनी के नियम अनुच्छेद 121 को लेकर है। ट्रस्ट का कहना है कि इस नियम के तहत ट्रस्ट के निदेशकों की बहुमत की मंजूरी आवश्यक है और निर्णायक मत के जरिए इस शर्त को दरकिनार नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखरन 63 वर्ष के हैं और उनका नया कार्यकाल 2032 तक प्रस्तावित है। टाटा समूह में कार्यकारी पदों पर सामान्यत: 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का नियम है। वर्ष 1987 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत करने वाले चंद्रशेखरन जनवरी 2017 में टाटा संस के अध्यक्ष बने थे।

विदेश यात्रा के लिए वॉट्सएप से खरीद सकेंगे ई-सिम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: संदेश भेजने वाले मंच वॉट्सएप ने विदेश यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए ई-सिम उपलब्ध कराने की नई सुविधा पर काम शुरू किया है। इसके जरिए उपयोगकर्ता वॉट्सएप से ही विदेश यात्रा के लिए ई-सिम खरीद सकेंगे और उसे अपने उपकरण में स्थापित कर सकेंगे। कंपनी का उद्देश्य यात्रियों को विदेश पहुंचने के बाद संपर्क सुविधा हासिल करने में होने वाली परेशानी से बचाना है।

कैलिक्स और एसोसिएटेड रोड कैरियर्स के प्रस्तावित विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने समारा वैकल्पिक निवेश निधि-स्कीम एक एलवीएफ, समारा वैकल्पिक निवेश निधि-तीन इंडिया, कैलिक्स कंटेनर टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड और एसोसिएटेड रोड कैरियर्स लिमिटेड से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत निवेश निधियों द्वारा कैलिक्स कंटेनर टर्मिनल्स में हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद कैलिक्स, एसोसिएटेड रोड कैरियर्स में हिस्सेदारी हासिल करेगी और दोनों कंपनियों के विलय का प्रस्ताव है। समारा वैकल्पिक निवेश निधि-स्कीम एक एलवीएफ और समारा वैकल्पिक निवेश निधि-तीन इंडिया सामूहिक रूप से समारा निवेश निधियों के रूप में कार्य करती हैं। ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वैकल्पिक निवेश निधि संबंधी नियमों के तहत पंजीकृत श्रेणी-दो की निवेश निधियां हैं। इनका प्रबंधन और सलाह समारा वैकल्पिक निवेश प्रबंधन एलएलपी द्वारा किया जाता है। कैलिक्स कंटेनर टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में वर्ष 2006 में स्थापित कंपनी है। यह कंटेनर माल परिवहन से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने के व्यवसाय में कार्यरत है।

देश की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 563 गीगावाट पहुंची, 55 प्रतिशत से अधिक क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों पर आधारित

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश के विद्युत क्षेत्र को मजबूत बनाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुधारों को गति देने के लिए विद्युत मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार को नई दिल्ली में शुरू हुआ। 27 और 28 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। इसमें 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्युत नियामक भाग ले रहे हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। देश ने विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय विद्युत जाल को मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। आगे विद्युत उत्पादन, ऊर्जा भंडारण, पारेषण और वितरण को एकीकृत प्रणाली के रूप में ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। राज्यों और विद्युत मंत्रालय की विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप बिजली वितरण कंपनियां लंबे समय बाद लाभ की स्थिति में पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि अगले दो दशकों में विद्युत क्षेत्र में लगभग 200 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों और निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक होगी।

मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सभी बिजली वितरण कंपनियों ने सामूहिक रूप से कर-पश्चात लाभ दर्ज किया है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए नीतिगत, परिचालन और नियामकीय सुधार जरूरी हैं। सम्मेलन में ऊर्जा भंडारण, संसाधन पर्याप्तता योजनाओं, अंतरराज्यीय एवं राज्यस्तरीय पारेषण, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना, स्मार्ट मीटर, फीडर पृथक्करण और परमाणु ऊर्जा स्थलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने राज्यों से कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं और अनुभव साझा करने का आग्रह किया। विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने बताया कि देश की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 563 गीगावाट हो गई है। इसमें 55 प्रतिशत से अधिक क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों पर आधारित है।

विद्युत क्षेत्र में अगले दो दशक में 200 लाख करोड़ के निवेश की संभावना: मनोहर लाल



एसटीपीआई का 75वां केंद्र शुरू तकनीकी उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

- 18.25 करोड़ रुपये की लागत से दो एकड़ में विकसित केंद्र से युवाओं नवउद्यमों और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मिलेंगे नए अवसर



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) ने बरेली में अपने 75वें केंद्र का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, राज्यसभा सांसद श्रुति गंगवार और एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लगभग 18.25 करोड़ रुपये के निवेश से दो एकड़ भूमि पर विकसित यह केंद्र क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों, नवउद्यमों और उभरते उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक होगा। इसके माध्यम से नवाचार, कौशल विकास, अनुसंधान और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

बरेली में एसटीपीआई केंद्र की स्थापना से रोहिलखंड क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। अब युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार, उद्यमिता और अनुसंधान से जुड़े अवसरों के लिए मुंबई, नोएडा और हैदराबाद जैसे शहरों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी। उन्हें अपने क्षेत्र में ही तकनीकी सुविधाएं और उद्यमिता के लिए सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा उद्यमियों द्वारा केंद्र का बेहतर उपयोग किए जाने पर भविष्य में सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से तकनीकी विकास तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि बरेली और आसपास के क्षेत्रों में प्रतिभा तथा उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं। यह केंद्र युवाओं और नवउद्यमों को नए विचार विकसित करने तथा आर्थिक विकास में योगदान देने का मंच उपलब्ध कराएगा। एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि देशभर में संगठन के 75 केंद्र हो चुके हैं, जिनमें से 67 छोटे और मध्यम शहरों में स्थित हैं। यह पहल प्रमुख महानगरों से आगे तकनीकी सुविधाओं का विस्तार करने और क्षेत्रीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

एआई से पांच साल में 2.4 करोड़ नौकरियों पर असर की आशंका

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते इस्तेमाल से आने वाले पांच वर्षों में दुनियाभर में करीब 2.4 करोड़ कार्यालय और ज्ञान आधारित काम करने वाले लोगों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। जेपी मॉर्गन वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले पांच वर्षों तक हर साल वैश्विक ज्ञान आधारित कार्यबल के करीब 1.3 प्रतिशत हिस्से पर इसका असर पड़ सकता है। कंपनियां कामकाज को स्वचालित करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल पर खर्च बढ़ा रही हैं। इस तकनीक के जरिए कर्मचारियों की तुलना में लगभग आधी लागत पर कुछ कार्य पूरे किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण रोजगार में बदलाव का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों को सीधे नौकरी से हटाने के बजाय खाली पदों पर नई नियुक्तियां नहीं करने के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि, यदि इसका असर किसी खास क्षेत्र या काम में अधिक केंद्रित हुआ, तो आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिका में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। यदि प्रभावित नौकरियों का दो-तिहाई हिस्सा अमेरिका में होता है, तो पांच वर्षों में करीब 1.6 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। इस हिसाब से हर साल लगभग 30 लाख कामों पर असर पड़ने का अनुमान है। यह अमेरिकी कार्यबल का करीब दो प्रतिशत होगा।

440 स्टार्टअप बदलेंगे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की तस्वीर

अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की तैयारी



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को बड़े आर्थिक अवसरों में बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2033 तक करीब 44 अरब डॉलर और 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना में निजी कंपनियों, नवोद्यमों, निवेशकों और तकनीकी संस्थानों की भूमिका अहम होने जा रही है। देश में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े करीब 440 नवोद्यम सक्रिय हैं, जो प्रक्षेपण यान, उपग्रह और अंतरिक्ष तकनीक के विकास में काम कर रहे हैं।

हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में आयोजित अंतरिक्ष सम्मेलन में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार और व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा हुई। इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने वैज्ञानिक उपलब्धियों को आर्थिक विकास में बदलने की संभावनाओं पर विचार किया।

अंतरिक्ष कारोबार का बड़ा हिस्सा केवल प्रक्षेपण यान और उपग्रह बनाने तक सीमित नहीं है। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल कृषि, मौसम, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इन सेवाओं के विस्तार से अंतरिक्ष आधारित कारोबार में बड़े आर्थिक अवसर पैदा होने की संभावना है। उपग्रहों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करके खेती की स्थिति, मौसम के बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं और परिवहन व्यवस्था की निगरानी में मदद मिल सकती है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनाने के अवसर भी बढ़ेंगे।

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के बाद नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिला है।

परेशानी

बाजार हिस्सेदारी घटकर 0.6 प्रतिशत रह गई...

स्पाइसजेट की आधी से अधिक उड़ानें प्रभावित, आर्थिक संकट से जूझ रही एयरलाइन

यात्रियों को उड़ान रद्द होने और धनवापसी में देरी की परेशानी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: स्पाइसजेट इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ने का असर उसके विमान परिचालन पर भी दिखाई दे रहा है। एयरलाइन अपनी आधी से अधिक उड़ानें संचालित नहीं कर पा रही है। इससे यात्रियों को उड़ानें रद्द होने, देरी और टिकट के पैसे वापस मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

देश की विमानन व्यवस्था में स्पाइसजेट की स्थिति लगातार कमजोर हुई है। वर्ष की शुरुआत में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी करीब चार प्रतिशत थी, जो सितंबर में घटकर केवल 0.6 प्रतिशत रह गई। कभी देश की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू विमानन कंपनी रही स्पाइसजेट के कई विमान खड़े हैं और परिचालन प्रभावित हो रहा है। हालांकि, इंडिगो और एअर इंडिया की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक होने के कारण देश के हवाई परिवहन पर व्यापक असर पड़ने की आशंका सीमित है।



5,500 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

कंपनी के संचालक मंडल ने 5,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए नए निवेशकों से बातचीत की जा रही है, हालांकि संभावित निवेशकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अगस्त में कंपनी ने दिवालिया होने से संबंधित एक याचिका पर समझौता कर राहत हासिल की थी। इसके बावजूद अन्य कानूनी मामले अभी जारी हैं।

नियामक ने मांगी परिचालन योजना

विमानन नियामक ने स्पाइसजेट से उसकी मौजूदा वित्तीय और परिचालन स्थिति पर जवाब मांगा है। साथ ही खड़े विमानों को दोबारा परिचालन में लाने की योजना भी मांगी गई है। जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने के बीच कंपनी की नई टिकट बुकिंग जारी रहने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई यात्री उड़ानों में गड़बड़ी और धनवापसी में देरी से परेशान हैं। पायलटों के एक संगठन ने भी एयरलाइन की तत्काल वित्तीय और सुरक्षा जांच की मांग की है। दूसरी ओर, ईरान युद्ध के कारण तेल और ईंधन की बढ़ती कीमतें कंपनी की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। आने वाले समय में बड़े मार्गों पर उच्च गति वाली रेल सेवाओं के विस्तार से विमानन कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है। ऐसे में विमानन क्षेत्र में मजबूत पूंजी, बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

कौशल प्रशिक्षण से युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, नव्या 2.0 आज से

नईदुनिया ब्यूरो, हरिद्वार: किशोरियों और युवतियों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार तथा उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नव्या 2.0 का शुभारंभ 28 नवंबर को हरिद्वार में किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय संयुक्त रूप से इस पहल का दूसरा चरण शुरू करेंगे। कार्यक्रम उत्तराखंड संस्कृत अकादमी सभागार में आयोजित होगा। इस पहल का विस्तार 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 जिलों तक किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से आकांक्षी और दुर्गम क्षेत्रों की युवतियों को शामिल किया जाएगा। योजना के तहत पात्र आयु सीमा 16 से 18 वर्ष से बढ़ाकर 16 से 25 वर्ष कर दी गई है।